



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 भाद्र 1934 (श0)

(सं0 पटना 416) पटना, बृहस्पतिवार, 23 अगस्त 2012

वित्त विभाग

अधिसूचनाएं

23 अगस्त 2012

सं0 को०प्र०/स्था०-03/2012-8738-वि०—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार लेखा सेवा नियमावली 2000 (यथा संशोधित 2011) को संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम एवं विस्तार :-

(i) यह नियमावली बिहार लेखा सेवा (संशोधन) नियमावली 2012 कही जा सकेगी ।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

2. उक्त नियमावली 2000 में प्रस्तावना की निम्नलिखित वाक्यों को एतद् द्वारा विलोपित किया जाता है - “ सेवा की मूल कोटि में प्रोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया पांच नियुक्ति वर्षों के बाद प्रारम्भ होगी और पांच नियुक्ति वर्षों तक मूल कोटि के सभी पद सीधी भर्ती द्वारा ही भरे जायेंगे । नियमावली के तत्संबंधी प्रावधान पांच नियुक्ति वर्षों के बाद ही प्रारम्भ होगी । ”

3. (i) उक्त नियमावली 2000 के नियम-6 के उप-नियम (i) के खण्ड (ख) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :- “(ख) अध्याय 4 (क) में उल्लिखित नियमों के अनुसार खुली प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा भर्ती । ”

(ii) उक्त नियमावली 2000 के नियम 6 के उप-नियम (i) के खण्ड (ग) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :- “ इस नियमावली के अध्याय-4 (ख) में उल्लिखित नियमों के खुली सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा भर्ती । ”

परन्तु वह व्यक्ति जो बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली 1958 के नियम 157 में विहित लेखा की अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ हो, इस सेवा में सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा भर्ती के लिए पात्र नहीं होगा ।

- परन्तु और कि कोई भी व्यक्ति सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा भर्ती के लिए तबतक पात्र नहीं होगा, जब तक वह अनुसूची-I में यथा उल्लिखित न्यूनतम अर्हक सेवा वर्षों को पूरा नहीं कर लिया हो ।”
4. उक्त नियमावली 2000 के नियम 8 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-
 “8- रिक्तियों का निर्धारण एवं आयोग को सूचित करना :- प्रत्येक वर्ष में 1ली अप्रिल तक राज्य सरकार उस वर्ष में सीधी भर्ती तथा सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से भरी जाने वाली रिक्तियों को निर्धारित करेगी तथा 30 अप्रिल तक निर्धारित रिक्तियों की सूचना आयोग को देगी। सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा भर्ती प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति नहीं समझी जाएगी तथा बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) संशोधन नियमावली 2007 के प्रावधान अनुसूची - 1 में वर्णित लेखा लिपिकों पर प्रभावी नहीं होंगे ।”
5. उक्त नियमावली 2000 के नियम 9 के उप-नियम (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा-“9-विकल्प द्वारा भर्ती:- बिहार वित्त सेवा में कार्यरत व्यक्ति इस सेवा के सदस्य के रूप में आने के लिए अपना विकल्प दे सकते हैं । यह विकल्प निम्नलिखित कोटि के पदों के लिए होगा - (क) मूल कोटि के पद- लेखा पदाधिकारी (9300-34800, ग्रेड पे- 4800) (ख) वरीय लेखा पदाधिकारी के पद (15600-39100 ग्रेड पे- 6600) (ग) उपायुक्त लेखा कोटि के पद (15600-39100 ग्रेड पे 7600) एवं (घ) संयुक्त आयुक्त लेखा कोटि के पद (37400-67000 ग्रेड पे- 8700) । यह समायोजन बिहार वित्त सेवा के वेतनमान में वेतन संरक्षण के साथ, इस सेवा में किया जायेगा । यह विकल्प सिर्फ एक बार, संशोधन की अधिसूचना के छः महीनों के भीतर, वित्त विभाग द्वारा प्राप्त किया जायेगा ।”
6. उक्त नियमावली 2000 के अध्याय 4 एवं 5 क्रमशः निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे :-

अध्याय - 4

(क) भर्ती : खुली प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा ।

11. सीधी भर्ती - आयोग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरने के लिए रिक्तियों को विज्ञापित करेगा और सेवा में नियोजन के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करेगा । बिहार लेखा सेवा के अधीन मूल पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उससे सम्बद्ध किसी संस्था से वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में स्नातक डिग्री प्राप्त होना अनिवार्य होगा तथा मुख्य परीक्षा में ऐच्छिक विषय के रूप में उक्त विषयों में से एक विषय लेना अनिवार्य होगा । वित्त विभाग आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के पदों पर 50 प्रतिशत की सीमा तक विशिष्ट अर्हता प्राप्त व्यक्तियों की सीधी नियुक्ति का निर्णय ले सकता है । ऐसी नियुक्ति आयोग द्वारा सिर्फ साक्षात्कार के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों में से की जायेगी ।
12. पात्रता - इस सेवा की मूल श्रेणी (बेसिक ग्रेड) में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की पात्रता बिहार सेवा संहिता 1952 के नियम 54 तथा इस नियमावली के नियम-11 में विहित अर्हता के अनुसार होगी । आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए अर्हताओं का निर्धारण, समुचित समय पर राज्य सरकार द्वारा किया जा सकेगा ।
13. चिकित्सा-परीक्षा - नियुक्ति के लिए चुने गए प्रत्येक अभ्यर्थी को राज्य सरकार द्वारा गठित चिकित्सक बोर्ड के समक्ष चिकित्सा-परीक्षा के लिए जाना होगा । पदीय कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में जो अभ्यर्थी अपनी अपेक्षित शारीरिक योग्यता के संबंध में चिकित्सा बोर्ड को संतुष्ट करने में असफल होगा उसे नियुक्त नहीं किया जायेगा । चिकित्सा बोर्ड स्वयं इसके लिए वस्तुनिष्ठ मापदंड निर्धारित करेगा ।
14. मौखिक जाँच- आयोग द्वारा संचालित की जाने वाली संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के संदर्भ में प्रावधान के अनुरूप ही अभ्यर्थियों को मौखिक जाँच में भाग लेने के लिए आयोग आमंत्रित करेगा तथा तदनुसार मौखिक जाँच हेतु अंक नियत किये जायेंगे ।
15. आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की अनुशंसा - आयोग द्वारा संचालित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के संदर्भ में प्रावधान के अनुरूप ही लिखित एवं मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आयोग एक मेधा सूची तैयार करेगा । वैसी तैयार की गयी सूची में से आयोग अभ्यर्थियों की उतनी संख्या की अनुशंसा राज्य सरकार को करेगा जितनी रिक्तियों की संख्या प्रतिवेदित की गयी हों । किसी अभ्यर्थी के योगदान न करने या रिक्तियों के बढ़ने की स्थिति में, एक वर्ष के भीतर या अगली विज्ञप्ति निकलने तक जो भी पहले हो, उसी मेधा सूची (पैनल) से अभ्यर्थियों की अनुशंसा की जा सकेगी ।”

16. वरीयता :- सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की आपसी वरीयता का निर्धारण आयोग द्वारा तैयार की गयी मेधा- सूची के अनुसार किया जायेगा ।

(ख) भर्ती : सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा

17. (i) अनुसूची-1 में सूचीबद्ध संवर्गों में से इस सेवा के मूल ग्रेड (बेसिक ग्रेड) में भर्ती सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा की जायेगी ।

(ii) सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सेवा की मूल ग्रेड में भर्ती हेतु अभ्यर्थियों को अनुसूची 1 में उल्लिखित अर्हता रखना अनिवार्य होगा ।

18. सीधी भर्ती एवं सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा भर्ती के बीच अनुपात- (i) पंचांग वर्ष के दौरान सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा भरे जाने वाले पदों की संख्या बेसिक सेवा ग्रेड में उपलब्ध कुल रिक्तियों की संख्या के पचीस प्रतिशत (अगले पूर्णांक तक बढ़ाकर) से अधिक नहीं होगी ।

(ii) राज्य सरकार, प्रत्येक कलेन्डर वर्ष के 1ली अप्रिल तक सीधी भर्ती एवं सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा पृथक रूप से भरे जाने वाले पदों की संख्या निर्धारित करेगी तथा 30 अप्रिल तक उसे आयोग को अधिसूचित कर देगी । परन्तु, किसी वर्ष में सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तिया वर्ष में रिक्तियाँ की कुल संख्या के 25 (पचीस) प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

(iii) उप-नियम (2) में निर्धारित रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती में सरकार की आरक्षण नीति लागू होगी ।

19. आयोग द्वारा संचालित सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित रिक्तियों को अनुसूची-I में यथोल्लिखित लेखा लिपिक संवर्ग के सफल घोषित सदस्यों से भरी जायेगी ।

20. अभ्यर्थियों की पात्रता - सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु अभ्यर्थियों की निम्नलिखित पात्रता होगी :-

(क) अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता स्नातक होगी ।

(ख) सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन के लिए नियत तिथि को अभ्यर्थियों को ग्रेड III में कम से कम दस वर्ष सेवा का अनुभव अवश्य प्राप्त हो ।

(ग) किसी अभ्यर्थियों को इस सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम तीन अवसर दिये जायेंगे ।

21. पाठ्यक्रम - सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम इस नियमावली की अनुसूची IV में यथाविहित होगी, राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उसमें संशोधन कर सकेगी ।

22. मौखिक परीक्षा- सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में कोई मौखिक जाँच नहीं होगी ।

23. न्यूनतम अर्हतांक - सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लिए, पैंतीस प्रतिशत तथा अन्य के लिए चालीस प्रतिशत होंगे । परन्तु सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सफल घोषित अभ्यर्थियों द्वारा सभी रिक्तियों के नहीं भरे जाने की दशा में ऐसी रिक्तियाँ अगले वर्ष की रिक्तियों में जोड़ी जायेंगी । ऐसी अग्रणीत रिक्तियाँ सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भर्ती के लिए आरक्षित नहीं की जायेगी । किंतु नियम-7 में उपबंधित आरक्षण लागू होगा ।

24. (i) आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार अभ्यर्थी अपना आवेदन प्रपत्र अपने कार्यालय प्रधान के माध्यम से आयोग को भेजेंगे ।

(ii) आयोग अपने द्वारा नियत परीक्षा फीस उदगृहित कर सकेगा ।

25. आयोग द्वारा अनुशंसा - (i) आयोग सफल अभ्यर्थियों का पैनाल मेधा क्रमानुसार तैयार करेगा । दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा समान अंक प्राप्त होने की दशा में, अभ्यर्थियों के उम्र के आधार पर वरीयता दी जायेगी अर्थात् कम उम्र के अभ्यर्थियों की तुलना में ज्यादा उम्र का अभ्यर्थी मेधा-सूची में उपर होगा । आयोग इस प्रकार तैयार की गयी मेधा सूची वित्त विभाग, बिहार सरकार को नियुक्ति की अनुशंसा के साथ उपलब्ध करायेगा ।

(ii) अपेक्षित संख्या में सफल अभ्यर्थियों के कमी या पदों पर योगदान न करने के चलते किसी विशिष्ट वर्ष में न भरी गयी रिक्तियों को अगले वर्ष की कुल रिक्तियों में जोड़ी जायेगी ।

अध्याय- 5**वरीयता,संपुष्टि एवं प्रोन्नति**

26. वरीयता - (i) इस नियमावली के अधीन आयोग की अनुशंसा पर इस सेवा में सीधी भर्ती द्वारा भर्ती किये गये सदस्यों की आपसी वरीयता आयोग द्वारा अनुशंसित मेधा सूची के अनुसार होगी ।

(ii) आयोग की अनुशंसा पर बेसिक ग्रेड में सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त इस सेवा का कोई भी सदस्य उसी वर्ष खुली प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त किसी व्यक्ति से वरीय होगा भले ही सीधी भर्ती की प्रक्रिया सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के पहले ही, पूर्ण कर ली गयी हो ।

स्पष्टीकरण - आयोग द्वारा अनुशंसित सूची में से कम से कम एक व्यक्ति की नियुक्ति से इस उप-नियम के प्रयोजनार्थ एक संव्यवहार समझा जायेगा ।

27. परिवीक्षा अवधि :- (i) किसी मौलिक रिक्ति के विरुद्ध नियोजन पर प्रत्येक पदाधिकारी को पदग्रहण की तिथि से दो वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा, परन्तु कोई व्यक्ति उस अवधि के दौरान कार्यकारी या अस्थायी हैसियत में पदधारित करता हो अधिकतम दो वर्षों के अध्यक्षीन, परिवीक्षा की अवधि की गणना, सरकार के आदेश से, की जा सकेगी ।

(ii) राज्यपाल, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार, परिवीक्षा अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति के समय, इस सेवा में सीधी भर्ती होने वाले किसी पदाधिकारी की नियुक्ति समाप्त कर सकेंगे अथवा सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्त किसी पदाधिकारी को उसके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित कर सकेंगे, यदि उक्त पदाधिकारी अपने परिवीक्षा की शर्तों को पूरा करने में असफल रहता हो अथवा इस सेवा में स्थायी नियुक्ति के लिए अन्यथा अयोग्य पाया जाता हो ।

(iii) राज्य सरकार इस सेवा के किसी पदाधिकारी की परिवीक्षा की अवधि को किसी युक्तियुक्त अवधि के लिए बढ़ा सकेगी ।

28. संपुष्टि - (i) परिवीक्षा पर नियुक्त किसी पदाधिकारी को परिवीक्षा-अवधि की समाप्ति पर संपुष्टि किया जा सकेगा, यदि वह विहित मानदंड के अनुसार विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका हो और यदि राज्य सरकार उसे संपुष्टि के योग्य समझे ।

(ii) इस सेवा में नियुक्त व्यक्ति को, उसकी भर्ती का जो भी श्रोत हो, किसी वेतन वृद्धि की निकासी स्वीकृति तब तक नहीं दी जायेगी, जब तक कि वह विहित मानदंड के अनुसार विभागीय परीक्षाओं में उत्तीर्ण न हो जाय ।

(iii) ऐसे मामलों में वेतन वृद्धि विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होने की तिथि से प्रभावी होगी ।

29. प्रोन्नति - इस सेवा की बेसिक ग्रेड से भिन्न सभी पद (आयुक्त लेखा प्रशासन और अध्याय-3 के नियम-9 एवं अध्याय-4 के नियम-11 द्वारा आच्छादित विनिर्दिष्ट मामलों के पदों को छोड़कर) इस सेवा के सदस्यों की प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे ।

30. विभागीय प्रोन्नति समिति - (i) संयुक्त आयुक्त एवं उपायुक्त के पदों पर प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित को मिलाकर गठित की जायेगी :-

(क) बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या आयोग के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत आयोग का कोई अन्य सदस्य-अध्यक्ष ।

(ख) प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार या उनके द्वारा मनोनीत उनके प्रतिनिधि जो विशेष सचिव से अन्यून पंक्ति के हों - सदस्य (पदेन)

(ग) आयुक्त, लेखा प्रशासन, बिहार - सदस्य (पदेन)

(घ) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी का कोई पदाधिकारी ।

(ii) वरीय लेखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु विचारण के लिए, सदस्य, राजस्व पर्षद की अध्यक्षता में एक प्रोन्नति समिति गठित की जायेगी और इसके अन्य सदस्य वही होंगे जो इस नियम के उप-नियम (i) में है ।

(iii) प्रोन्नति की अर्हता और प्रक्रिया वही होगी जो अन्य राज्य सेवाओं के लिए निर्धारित हो, यदि इस सेवा के लिए कोई भिन्न अर्हताएँ और प्रक्रिया निर्धारित न की गयी हो । इस सेवा में पदों पर प्रोन्नति वाले पदों के लिए न्यूनतम अर्हक कालावधि अनुसूची-II में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार निर्धारित की जायेगी ।

7. उक्त नियमावली 2000 की अनुसूची I निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :
निम्नलिखित पदों से बिहार लेखा सेवा के बेसिक ग्रेड में सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भर्ती की जायेगी -
कोषागारों, भविष्य निधि कोषांगों तथा अन्य विभागों के लेखा संवर्ग के कर्मचारी जिन्हें सरकारी सेवा में कम से कम 10 वर्षों का अनुभव हो ।
8. उपर्युक्त संशोधन उक्त नियमावली 2000 के प्रवृत्त होने की तिथि से प्रभावी होंगे । किंतु किसी सरकारी कर्मी को मूल नियमावली के प्रावधानों के अधीन कोई लाभ दिया गया हो तो वह इस संशोधन नियमावली से प्रभावी नहीं होगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रामेश्वर सिंह,
प्रधान सचिव ।

The 23rd August 2012

No. Ko. Pra./Stha.-03/2012-8738-F—In exercise of power conferred by provision to Article 309 of the constitution of India, Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend. The Bihar Accounts Service Rules. 2000 (as amended in 2011).

1. *Short Title and extent—(i) These rules may be called Bihar Accounts Service Rules (Amendment) Rules 2012.*

(ii) It shall extend to the whole of the state of Bihar.

2. *Following lines of preamble of the said Rules 2000 are hereby deleted:-*

"The process of recruitment to the basic grade of service shall commence after five recruitment years and for the first five recruitment years. all posts of the basic grade shall be filled by direct recruitment. Provisions of the Rules related to the above shall be effective only after five recruitment years."

3. (i) Clause (B) of sub Rule (i) of Rule 6 of said Rules 2000 shall be substituted by the following :-

"Recruitment by open competitive examination in accordance with rules mentioned in chapter 4 (A)."

(ii) Clause (c) of sub Rule (i) of Rule 6 of said Rules 2000 shall be substituted by the following :-

"Recruitment by Limited Competitive Examination in accordance with rules mentioned in chapter 4 (B)."

Provided the person who has not passed the final examination in Accounts prescribed in Rule 157 of the Board's miscellaneous Rules 1958 shall not be eligible for recruitment by Limited Competitive Examination.

Provided further that a person shall not be eligible for recruitment by Limited Competitive Examination unless he has completed the minimum qualifying years of service as mentioned in Schedule I.

4. Rule 8 of said Rules 2000 shall be substituted by the following :-

8. Determination of vacancies and notifying the same to the commission- The State Government shall determine the number of vacancies to be filled up that year by direct recruitment and recruitment by limited competition examination by 1st April and give notice of the vacancies so determined to the commission by 30th April. Recruitment by limited Competitive Examination shall not be deemed as appointment by promotion and provisions of ACP (Assured Career Progression) (Amendment) Rule 2007 shall not be applicable to Accounts Clerks as mentioned in Schedule-I.

5. *Sub Rule (1) of Rule 9 of the said Rules 2000 shall be substituted by the following*
:- 9. Recruitment by option- A person serving in the Bihar Finance Service may exercise his option to be considered as a member of this service. This option may be available for following grades:- (a) Basic grade:- Accounts Officer (9300-34800 Grade pay-4800); (b) Post of Senior Accounts Officer (15600-39100 Grade pay 6600); (c) Posts of Deputy Commissioner Accounts category (37400-67000 Grade pay 8700) and the posts of Joint Commissioner Accounts category (37400-67000, Grade Pay 8700) This adjustment shall be done in this service in pay scale of Bihar Finance Service with pay protection. This option shall be obtained by Finance Department only once within six months of notification of amendment.

6. *Chapter 4 and 5 of said Rules 2000 shall be substituted by the following respectively:-*

Chapter-4

(A) Recruitment : By open competitive examination.

11. *Direct Recruitment* :- The commission shall advertise the vacancies to be filled by direct recruitment through combined competitive examination and shall invite applications from candidates eligible for appointment to Service. It will be essential for candidates for appointment on basic post under Bihar Accounts Service to have Bachelor's degree in Commerce, Economics, Mathematics or Statistics from a recognized university or an institution affiliated to it and in main examination it will be compulsory for candidates to take one of said subjects as optional subject. Finance Department may take decision to appoint specially qualified persons by direct recruitment against 50% posts of Internal Finance Advisors; such appointments shall be made from amongst the candidates selected on the basis of interview only.

12. *Eligibility* :- The candidates' eligibility for appointment to the basic grade of the Service shall be in accordance with Rule 54 of the Bihar Service Code, 1952 and qualifications prescribed in Rule 11 to this Rule. Qualification for direct appointment to the posts of Internal Finance Advisors may be determined by the State Government at the appropriate time.

13. *Medical Examination* :- Every candidate selected for appointment shall have to undergo a medical examination before the Medical Board constituted by the State Government. A candidate, who fails to satisfy the Medical Board in regard to his/ her physical fitness necessary for efficient performance of the duties of the post, shall not be appointed. The Medical Board shall determine objective standards for this.

14. *Viva - Voce Test* :- The Commission shall invite candidates for Viva-Voce test in conformity with the provision in the context of combined competitive examination to be conducted by the commission and marks for Viva- Voce test shall also be fixed accordingly.

15. *Recommendation of candidates by the Commission* :- The Commission shall prepare a merit list on the basis of marks obtained in written examination and viva-voce test in conformity with the provision in context of combined competitive examination conducted by the Commission. From the merit list so prepared, the commission shall recommend such number of candidates, the Government as number of vacancies are reported. In case of non- joining of any candidate or increase in vacancies, the recommendation of candidates may be made from the same merit list (panel), within one year or next advertisement whichever takes place earlier.

16. *Seniority* :- The inter-se seniority of the employees appointed by direct recruitment shall be determined in accordance with the merit list prepared by the Commission.

(B) Recruitment : By Limited competitive examination

17-(i) Recruitment to the basic grade of this service by limited competitive examination shall be made from amongst the cadres listed in schedule I.

(ii) For Recruitment to the basic grade of the service by limited competitive examination, candidates must possess qualification mentioned in schedule I.

18. *Ratio Between Direct Recruitment and Recruitment by Limited Competitive Examination* :- (i) The number of posts to be filled by limited competitive examination shall not exceed 25 (twenty five) percent (rounded off to the next higher whole number) of the total number of vacancies available in the basic grade of the Service during the calendar year.

(ii) The State Government shall determine, by 1st April of every calendar year, the number of posts to be filled, separately by direct recruitment and by limited competitive examination and notify the same to the commission by 30th April. Provided that the vacancies to be filled up by recruitment through limited competitive examination shall not exceed 25 (twenty five) percent of the total number of vacancies in the year.

(iii) Reservation policy of the Govt. shall be applicable in the recruitment against the vacancies in Sub-Rule (2).

19. Vacancies decided by Government will be filled up from the members of the Accounts Clerk cadre as mentioned in schedule I declared successful on the basis of limited competitive examination conducted by the Commission.

20. Eligibility of Candidates :-

(a) Minimum education qualification of candidate will be graduation.

(b) The candidate must have experience of ten years service in grade III on the date fixed for holding of Limited Competitive Examination.

(c) A candidate will be allowed the maximum of three opportunities to appear in the limited competitive examination.

21. *Syllabus*:- Syllabus for limited competitive examination will be as prescribed in Schedule IV of those Rules, the State Government may amend it, by notification in the official gazette.

22. *Viva - Voce* :- There will be no Viva- Voce examination in limited competitive examination.

23. *Minimum Qualifying Marks* :- The minimum qualifying marks for the written test in the limited competitive examination shall be 35 percent for Scheduled Tribe and Scheduled Caste candidates and 40 percent for others.

Provided that, in case all vacancies are not filled up by candidates declared successful on the basis of the limited competitive examination, such vacancies shall be added to the vacancies of next year. Such carried over vacancies shall not be reserved for recruitment on the basis of limited competitive examinations but the reservation provided for in Rule 7 shall apply.

24. (i) Candidates shall send their application forms to the Commission through head of their office as per the advertisement published by the Commission.

(ii) Commission can levy examination fee as fixed by it.

25. Recommendation by Commission :-

(i) The Commission shall prepare the panel of successful candidates for the appointment in order of merit. In case, equal marks are obtained by two or more candidates, weightage will be given on the basis of the age of the candidates in the merit list i.e. the candidate of higher age will be placed higher in the merit list as compared to the lower age candidates. The Commission will make available the merit list, so prepared, to the Finance Department, Government of Bihar with the recommendation for appointment.

(ii) Vacancies not filled up in a particular year due to lack of required number of successful candidates or non- joining the posts, shall be added to the total number of vacancies next year.

Chapter 5**Seniority, confirmation and promotion**

26. Seniority :- (i) The Inter-se-seniority among the members of the Service recruited directly on the recommendation of the Commission in the service will be in accordance with the merit list recommended by the Commission.

(ii) A member of the Service appointed to the basis grade on the recommendation of the commission on the basis of limited competitive examination shall rank senior to any person appointed by open competitive examination in that year even if the process of direct recruitment has been completed earlier than that of limited competitive examination.

Explanation :- For the purpose of this sub-rule, a transaction will be deemed to have taken place with the appointment of at least one person from the list recommended by the Commission.

27. Probation :-(i) Every Officer shall, on appointment against a substantive vacancy, be on probation for a period of two years from the date of joining the post.

Provided that the period during which a person has held that post in officiating or temporary capacity may, subject to a maximum of two years, be allowed, by the Government, to be counted towards the period of probation.

(ii) The Governor may, during or at the end of the period of probation, terminate the appointment of an officer directly recruited to the Service or revert an officer appointed by limited competitive examination to his substantive appointment, in accordance with the provisions contained in the Bihar Government Servant (Classification, control and appeal) Rules 2005, if the said officer has failed to fulfill the conditions of his Probation or is found to be otherwise unfit for permanent appointment to the service.

(iii) The State Government may, extend the period of probation of an officer of this service for a reasonable period.

28. Confirmation :-(i) An officer appointed on probation shall be confirmed at the end of the period of probation, if he has passed the departmental examination in accordance with the prescribed standard and if the State Government considers him fit for confirmation.

(ii) No Person, appointed to this Service regardless of the source of recruitment shall be permitted to draw any increment, until he clears the departmental examinations in accordance with the prescribed standard.

(iii) In such cases, increment will be effective from the date of the passing of departmental examination.

(29) *Promotion* :- All posts other than those in the basic grade of the service (except the post of commissioner Accounts Administration, and specific matter covered by Rule 9 of chapter 3 and Rule 11 of chapter 4) shall be filled up by promotion to members of this service.

30. *Departmental Promotion Committee*:- (i) Departmental Promotion Committee for considering Promotion to the post of Joint Commissioner and Deputy Commissioner shall be constituted consisting of the following :-

(a) Chairman of Bihar Public Service Commission or any other member of the commission nominated by the Chairman-----Chairperson.

(b) Principal Secretary/Secretary, Finance Department, Government of Bihar or any officer nominated by him as his representative not below the rank of Special Secretary--Member (Ex- Officio)

(c) Commissioner, Account Administration, Bihar-- Member (Ex-Officio)

(d) Any officer of Scheduled Castes/ Scheduled Tribes category nominated by the Department of General Administration.

(ii) For consideration of promotion to the post of Senior Accounts Officer, a promotion committee shall be constituted under the chairmanship of the Member Board of Revenue, its other members will be same as in sub-rule (i) above.

(iii) Qualification and procedure for the promotion will be same as is determined for other State Services if different qualifications and procedure are not determined for this Service. The minimum qualification period of kalawadhi for promotional posts shall be determined according to provisions mentioned in schedule II.

7. *Schedule 1 of the said Rules 2000 shall be substituted by the following:-*

Recruitment to the basic grade of Bihar Accounts Service on the basis of Limited Competitive Examination shall be done from following posts :-

(a) Employees of accounts clerks cadre working in Treasuries, Provident Funds cells and in other departments having at least 10 years of experience in Government Service.

8. Above said amendments shall be effective from the date of commencement of the said Rules 2000 but any benefit which has been awarded to any Government employee under provisions of the original Rules, shall not be affected by these amended rules.

By order of the Governor of Bihar,
RAMESHWAR SINGH,
Principal Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 416-571+100-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>